Indian sedimentary basin and find out oil here so that we become oil sufficient and our country can strengthen itself as far as oil security is concerned.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, in the reply two expressions have been used — "New Exploration Licensing Policy 2009" and "production sharing contract". My question is: (a) Who owns the petroleum products of the country? (b) Does the Government have any standard production sharing contract? ..*(Interruptions)*.. (c) Is the contractor entitled only to contract price or also a share in the ownership of the product? Please clarify it.

SHRI JITIN PRASADA: Sir, as far as the New Exploration Licensing Policy which was started in 1999 is concerned, bidding of oil blocks and gas blocks under this policy from then onwards is subject to a profit-sharing contract. In that profit-sharing contract, a contractor is given the mandate to explore and find out whether there is any commercial viability with regard to oil or gas. Whatever expenses are incurred in finding out or searching oil, they are reimbursed. That is how there is a share of the Government and of the contractor with regard to the profit that comes which is known as the profit petroleum. That only comes when oil or gas is commercially viable.

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, our State, Tripura, is floating over gas and there is a high potential to explore gas from here and there. But the thing is that ONGC is minimising its period of exploration so the seasonal workers who depend on this work get less than six months' work in a year. So, my request is to give more time for exploration. As there is potential it will to serve the seasonal workers in the right earnest.

SHRI MURLI DEORA: Sir, I am very happy to inform the hon. Member that as per the request of the Government of Tripura, the ONGC has cleared power plant there. Though the cost of power transmission was very high, but in order to help the small State of Tripura, the ONGC has agreed to put up a small power plant which will be able to use their gas.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I would only like to thank the hon. Minister for this.

SHRI MURLI DEORA: You intervened; that is why, it happened.

SHRI MATILAL SARKAR: No; no intervention... *(Interruptions)*.

MR. CHAIRMAN: Mr. Sarkar, your question is over. Question No. 163.

पंजाब में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन

*163. **श्री अवतार सिंह करीमपुरी**: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) के अंतर्गत पंजाब को अब तक आवंटित की गई धन-राशि का वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्य में सृजित रोजगार के अवसरों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) राज्य में इस योजना में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में अब तक प्राप्त हुई शिकायतों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक लंबित शिकायतों का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सी.पी. जोशी): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) निधियों के केंद्रीय हिस्से की रिलीज का वर्षवार एवं जिलावार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। (नीचे **देखिए**) राज्य में जिन परिवारों को रोजगार दिया गया, उनकी कुल संख्या विवरण-II में दी गई है। (नीचे **देखिए**)

(ग) और (घ) पंजाब में नरेगा के कार्यान्वयन में अनियमितताओं संबंधी आठ शिकायतें इस मंत्रालय में प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु राज्य सरकार को भेजा गया था। दो शिकायतों के संबंध में कार्रवाई पूरी हो गई है। शेष 6 शिकायतें राज्य सरकार में लम्बित हैं। जिलावार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

जारी की गई निधियों का वर्षवार और जिलावार ब्यौरा

(लाख रु में)

क्र. सं.	जिले	2006-07				2007-08				2008-09				2009-10 (अक्टूबर, 09 तक)			
		केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधि	कुल व्यय	अंतशेष	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधि	कुल व्यय	अंतशेष	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधि	कुल व्यय	अंतशेष	केन्द्रीय रिलीज (आदिनांक)	कुल उपलब्ध निधि	कुल व्यय	अंतशेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	होशियारपुर	2755.75	3839.21	2500.21	1339.00	380.15	2183.59	1676.93	506.66	1862.53	2567.72	2061.22	506.50	1738.60	2245.10	1411.65	833.45
2.	अमृतसर					1096.28	1466.93	1086.84	380.09	721.92	1256.29	1132.64	123.65	600.00	814.95	514.02	300.93
3.	जालंधर					504.59	918.53	102.80	815.73	0.00	815.73	193.71	622.02	0.00	622.02	204.55	417.47
4.	नवांशहर					49.30	456.31	137.72	318.59	0.00	318.59	252.27	66.32	212.47	278.79	250.57	28.22
5.	बरनाला									279.24	395.68	279.17	116.51	0.00	116.51	113.90	2.61
6.	भंटिडा									491.53	705.05	465.25	239.80	737.40	1143.20	533.68	609.52
7.	फरीदकोट									116.66	141.62	46.18	95.44	73.23	192.08	91.54	100.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.	फतेहगढ़ साहेब									89.58	211.01	142.90	68.11	67.05	136.31	86.97	49.34
9.	फिरोजपुर									205.75	313.95	133.47	180.48	150.00	330.48	325.12	5.36
10.	गुरदासपुर									309.02	540.12	385.73	154.39	413.10	607.64	502.92	104.72
11.	कपूरथला									95.89	104.71	69.24	35.47	60.00	95.47	69.88	25.59
12.	लुधियाना									170.83	402.07	100.79	301.28	71.70	372.98	240.81	132.17
13.	मानसा									403.93	445.73	196.58	249.15	312.93	562.17	284.18	277.99
14.	मोगा									92.95	104.19	93.86	10.33	20.97	32.00	29.18	2.82
15.	मुक्तसर									233.98	400.44	240.89	159.55	311.72	471.27	459.24	12.03
16.	पटियाला									480.48	639.02	284.84	354.18	316.54	670.72	260.56	410.16
17.	रूपनगर									242.52	434.57	124.12	310.45	22.00	332.45	277.84	54.61
18.	संगरूर									689.20	1091.99	707.56	384.43	239.65	624.08	377.68	246.40
19.	एसएएस नगर									154.95	251.38	230.79	20.59	0.00	41.18	20.59	20.59
20.	तरनतारन									134.36	150.82	94.60	56.22	50.00	106.22	56.11	50.11
	कुल	2755.75*	3839.21	2500.21	1339.00	2030.32	5025.36	3004.29	2021.07	6775.32	11290.68	7235.81	4054.87	5397.36	9795.62	6110.99	3684.63

*इसके अलावा, चरण II में कवर किए गए अमृतसर, जालंधर तथा नवांशहर को प्रारंभिक गतिविधियों के लिए क्रमशः 130 लाख रु., 230 लाख रु तथा 330 लाख रु. जारी किए गए। इस प्रकार 2006-07 में पंजाब को कुल रिलीज 3445.75 लाख रु. थी।

अभ्युक्ति : कुल उपलब्ध निधियों में वर्ष के दौरान केन्द्रीय रिलीज, राज्य रिलीज, विविध प्राप्तियां, पिछले वर्ष जारी परंतु इस वर्ष में प्राप्त निधियां शामिल हैं।

विवरण-II

रोजगार पाने वाले परिवारों का ब्यौरा

क्र. सं.	जिला	2006-07 परिवारों की संख्या जिन्हें रोजगार दिया गया	2007-08 परिवारों की संख्या जिन्हें रोजगार दिया गया	2008-09 परिवारों की संख्या जिन्हें रोजगार दिया गया	2009-10 (अक्तू., 09 तक) परिवारों की संख्या जिन्हें रोजगार दिया गया
	चरण-1 **(2.2.06 से)**				
1.	होशियारपुर	31648	26297	35512	25096
	चरण-2 **(1.4.07 से)**				
2.	अमृतसर	15555	14913	5774	15555
3.	जालंधर	3111	4234	3288	3111
4.	नवांशहर	4727	4154	5165	4727
	चरण-3 **(1.4.08 से)**				
5.	बरनाला			1268	1127
6.	भंटिडा			17036	8986
7.	फरीदकोट			5319	1850
8.	फतेहगढ़ साहेब			1955	1581
9.	फिरोजपुर			9943	8617
10.	गुरदासपुर			7036	12804
11.	कपूरथला			2566	1139
12.	लुधियाना			996	5023
13.	मानसा			7241	3681
14.	मोगा			1703	932
15.	मुक्तसर			11259	10635
16.	पटियाला			4398	5756
17.	रूपनगर			1046	2778
18.	संगरूर			11652	28780
19.	एसएएस नगर			5763	515
20.	तरनतारन			1908	1521
	कुल	31648	49690	149902	135048

विवरण-III

पंजाब में नरेगा के अंतर्गत शिकायतों की स्थिति

क्र. सं.	जिला	शिकायतकर्ता का नाम	लगाए गए आरोप	मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई	की गई कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार की रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6
1.	अमृतसर तथा जालंधर	दिनांक 6.11.2009 की समाचार पत्र कतरन किसका शीर्षक था "केंद्र रोजगार की गारंटी देता है, परंतु पंजाब रोजगार नहीं देता"	विशेष रूप से अमृतसर तथा जालंधर जिलों में बीडीओ, पंचायत सचिवों एवं सरपंचों के खराब कार्य-निष्पादन के कारण नरेगा निधियों का कम उपयोग	मामले को 21.11.2007 को राज्य सरकार को भेजा गया था	राज्य ने सूचित किया है कि अमृतसर तथा जालंधर को 2007-08 में कवर किया गया है। प्रारंभिक तथा अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के कारण चरण-II जिले में क्षेत्र में कार्य नवम्बर, 2007 में शुरु किया गया था। अब कार्य तेजी से हो रहा है और पिछले तीन महीनों में इसमें बहुत सुधार हुआ है। फरवरी, 2008 तक कुल 5081.58 लाख रु. की उपलब्ध निधियों में से 2371.86 लाख रु. (47%) की राशि उपयोग कर ली गई है और 15.12 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए हैं।
2.	फिरोजपुर तथा तरनतारन	श्री जय सिंह, अध्यक्ष, दलित दासता विरोधी आंदोलन, जालंधर	फिरोजपुर तथा तरनतारन जिले में जीरा घल खुर्द तथा पट्टी ब्लॉक में पंजीकरण हेतु आवेदन स्वीकार करने और पात्र परिवारों को जॉब कार्ड जारी करने से इंकार करना	मामले को 16.6.08 को राज्य सरकार को भेजा गया था। एनएलएम की नियुक्ति की गई थी। जिसने आरोपों को सही नहीं पाया है।	राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शिकायत को आधारहीन पाया गया है।
3.	होशियारपुर	श्री रोशन लाल तथा अन्य,	• जॉब कार्डों में जाली प्रविष्टि	राज्य सरकार से 5.5.2009	एडीसी (विकास), होशियारपुर ने बताया है

1	2	3	4	5	6
		गम्बोवाल, तहसील- ¤सूहा, जिला-होशियारपुर	• सरपंच द्वारा जॉब कार्ड अपने पास रखना • लोगों को काम न दिया जाना।	को जांच हेतु अनुरोध किया गया था।	कि एसडीएम, दसुहा को जांच की जिम्मेवारी दी गई थी। एसडीएम, दसुहा ने सूचित किया है कि एनआरईजीएस के अंतर्गत ग्राम पंचायत को 4.90 लाख रु. दिए गए थे। सभी 53 जॉब कार्डधारियों को रोजगार दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा बाहर से कोई मजदूर नहीं लिया गया था। सभी 14 शिकायतकर्ताओं को मांग पर रोजगार दिया गया। एडीसी (विकास) ने यह भी बताया है कि शिकायत दोनों पक्षों के बीच आंतरिक लड़ाई के कारण होती गई थी। उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि शिकायत को फाईल कर दिया जाए।
4.	जालंधर	श्री रंजीत सिंह सुपुत्र श्री केवल सिंह, ग्राम पंचायत, कोर्ट खुर्द, तहसील, जिला जालंधर (पूर्व), पंजाब	सरपंच, श्री प्रवीन कुमार द्वारा 2 लाख रु. की निधि का दुरुपयोग।	राज्य सरकार से 23.6-.2009 को जांच हेतु अनुरोध किया गया था।	जांच एडीसी (विकास), जालंधर को सौंपी गई थी जिन्होंने अपने दिनांक 25.11.09 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि एनआरईजीएस के तहत ग्राम पंचायत कोट खुर्द द्वारा कार्यान्वित कार्य की अधिशासी अभियंता, पंचायती राज, जालंधर द्वारा जांच की गई थी और इसे सही पाया गया था। कार्य की सामाजिक लेखा परीक्षा भी की जा चुकी है। इस प्रकार, शिकायत बेबुनियाद है और इसे फाईल कर दिया जाए।
5.	जालंधर	श्री रंजीत सिंह सुपुत्र श्री केवल सिंह, ग्राम पंचायत, कोट खुर्द, ब्लॉक पूर्व, जिला जालंधर।	श्री प्रवीन कुमार, ग्राम पंचायत, कोट खुर्द के स्थान पर अन्य गांव कुमर पिंड में सड़क के निर्माण की अनुमति देकर निधियों का दुरुपयोग करना।	राज्य सरकार से 6.7-.2009 को जांच हेतु अनुरोध किया गया था।	

1	2	3	4	5	6
6.	संगरूर	श्री विजय इन्दर सिंगला, संसद सदस्य (लोक सभा)	निधियों का उपयुक्त वितरण न करना, जिला संगरूर, पंजाब मे नरेगा योजना के अंतर्गत कोई कार्य उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा आंकड़ों की प्रविष्टि का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।	राज्य सरकार से 07.11.2009 जांच हेतु अनुरोध किया गया।	एडीसी (विकास), संगरूर ने सूचित किया है कि जिला वार्षिक आधार पर पंचायत-वार श्रम बजट तैयार करता है और भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने पर उन्हें ग्राम पंचायत अधिकारियों (नरेगा) को वितरित किया जाता है। संगरूर जिले में 549 परिवारों को रोजगार दिया गया है और 71893 रोजगार श्रमदिवस सृजित किए गए हैं।
7.	जालंधर	श्री जय सिंह, अध्यक्ष, नरेगा वर्कर्स यूनियन, बी-1/665, रंजीतगढ़ गुरुद्वारा रोड, फिल्लौर, जिला जालंधर द्वारा श्रीमती चरणजीत कौर, तथा नरेगा वर्कर्स यूनियन की शिकायतें भेजी गई हैं।	गांव सारावान बोदला, ब्लॉक मलौत, जिला मुक्तसर, पंजाब में मजदूरी के भुगतान में विलम्बा नरेगा, 2005 का उल्लंघन तथा जिला तरनतारन के पट्टी ब्लॉक में सुभ्रा गांव में जॉब कार्ड जारी न किया जाना।	राज्य सरकार से 22.10.2009 को जांच हेतु अनुरोध किया गया था।	शिकायत को एडीसी (विकास), जालंधर को भेजा गया था जिन्होंने सूचित किया है कि यह मामला जिला मुक्तसर से संबंधित है। अब इस मामले को एडीसी (विकास), मुक्तसर को जांच के लिए भेज दिया गया है।
8.	फिरोजपुर	श्री साहिब राम कदवासरा, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत-रामसरा, तहसील-अबोहर, जिला-फिरोजपुर	जाली जॉब कार्डों के बारे में।	राज्य सरकार से 20.8.2009 को जांच हेतु अनुरोध किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित है।

Implementation of NREGS in Punjab

†*163. SHRI AVTAR SINGH KARIMPURI: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of amount allocated, till date, to Punjab under the National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS), year-wise and district-wise;

(b) the total number of jobs created in the State under NREGS, district-wise;

(c) the details of complaints received so far regarding irregularities in the Scheme, in the State, district-wise; and

(d) the details of complaints which are still pending, district-wise?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI C.P. JOSHI): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) NREGS is demand driven and not an allocation based programme. Year-wise and district-wise release of Central share of funds is given at Statement-I (*See* below). The total number of households provided employment in the State is given in Statement-II (*See* below).

(c) and (d) Eight complaints regarding irregularities in the implementation of NREGS in Punjab have so far been received in this Ministry. These complaints were forwarded to the State Government for appropriate action. Action has been completed in respect of six complaints. The remaining two complaints are pending in the State Government. District-wise details are given in Statement-III (*See* below).

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

Statement-I

Year-wise and District-wise details of funds released

(In lakhs)

Sl. No.	Districts	2006-07				2007-08				2008-09				2009-10 (upto Oct., 09)			
		Central Release	Total Available Funds	Total Expen-diture	Closing Balance	Central Release	Total Available Funds	Total Expen-diture	Closing Balance	Central Release	Total Available Funds	Total Expen-diture	Closing Balance	Central Release	Total Available Funds	Total Expen-diture	Closing Balance
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Hoshiarpur	2755.75	3839.21	2500.21	1339.00	380.15	2183.59	1676.93	506.66	1862.53	2567.72	2061.22	506.50	1738.60	2245.10	1411.65	833.45
2.	Amritsar	1096.28	1466.93	1086.84	380.09	721.92	1256.29	1132.64	123.65	600.00	814.95	514.02	300.93				
3.	Jalandhar	504.59	918.53	102.80	815.73	0.00	815.73	193.71	622.02	0.00	622.02	204.55	417.47				
4.	Nawanshahar	49.30	456.31	137.72	318.59	0.00	318.59	252.27	66.32	212.47	278.79	250.57	28.22				
5.	Barnala					279.24	395.68	279.17	116.51	0.00	116.51	113.90	2.61				
6.	Bathinda					491.53	705.05	465.25	239.80	737.40	1143.20	533.68	609.52				
7.	Faridkot					116.66	141.62	46.18	95.44	73.23	192.08	91.54	100.54				
8.	Fatehgarh Sahib					89.58	211.01	142.90	68.11	67.05	136.31	86.97	49.34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9.	Firozepur									205.75	313.95	133.47	180.48	150.00	330.48	325.12	5.36
10.	Gurdaspur									309.02	540.12	385.73	154.39	413.10	607.64	502.92	104.72
11.	Kapurthala									95.89	104.71	69.24	35.47	60.00	95.47	69.88	25.59
12.	Ludhiana									170.83	402.07	100.79	301.28	71.70	372.98	240.81	132.17
13.	Mansa									403.93	445.73	196.58	249.15	312.93	562.17	284.18	277.99
14.	Moga									92.95	104.19	93.86	10.33	20.97	32.00	29.18	2.82
15.	Muktsar									233.98	400.44	240.89	159.55	311.72	471.27	459.24	12.03
16.	Patiala									480.48	639.02	284.84	354.18	316.54	670.72	260.56	410.16
17.	Rupnagar									242.52	434.57	124.12	310.45	22.00	332.45	277.84	54.61
18.	Sangrur									689.20	1091.99	707.56	384.43	239.65	624.08	377.68	246.40
19.	SAS Nagar									154.95	251.38	230.79	20.59	0.00	41.18	20.59	20.59
20.	Tarantaran									134.36	150.82	94.60	56.22	50.00	106.22	56.11	50.11
	TOTAL	2755.75*	3839.21	2500.21	1339.00	2030.32	5025.36	3004.29	2021.07	6775.32	11290.68	7235.81	4054.87	5397.36	9795.62	6110.99	3684.63

*In addition Rs.130 lakh were released to Amritsar, Rs.230 lakh to Jalandhar Rs.330 lakh to Nawashahar covered in phase-II for preparatory activities. Total release to Punjab in 06-07 was thus Rs. 3445.75 lakh

Remarks: Total available funds include central releases, State releases, miscellaneous receipts during the year, funds released in the previous year put received during the year and carry over balance.

Statement-II

Details of the families provided employment

Sl. No.	District	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 upto Oct, 09
		No. of households provided employment	No. of households provided employment	No. of households provided employment	No. of households provided employment
	Phase-I with effect from 2.2.06				
1.	Hoshiarpur	31648	26297	35512	25096
	Phase-II with effect from 1.4.07				
2.	Amritsar		15555	14913	5774
3.	Jalandhar		3111	4234	3288
4.	Nawanshahr		4727	4154	5165
	Phase-III with effect from 1.4.08				
5.	Barnala			1268	1127
6.	Bathinda			17036	8986
7.	Faridkot			5319	1850
8.	Fatehgarh Sahib			1955	1581
9.	Firozepur			9943	8617
10.	Gurdaspur			7036	12804
11.	Kapurthala			2566	1139
12.	Ludhiana			996	5023
13.	Mansa			7241	3681
14.	Moga			1703	932
15.	Muktsar			11259	10635
16.	Patiala			4398	5756
17.	Rupnagar			1046	2778
18.	Sangrur			11652	28780
19.	SAS Nagar			5763	515
20.	Tarantaran			1908	1521
	TOTAL	31648	49690	149902	135048

Statement-III

Status of complaints under NREGS in Punjab

Sl. No.	District	Name of the complainant	Allegations made	Action taken by Ministry	Action reported by State Government
1	2	3	4	5	6
1.	Amritsar and Jalandhar	Newspaper clipping dated 06.11.07 titled "Centre guarantees jobs, but Punjab doesn't give any"	Poor utilization of NREGA funds due to dismal performance of the BDOs, Panchayat Secretaries and Sarpanches, particularly in Amritsar and Jalandhar districts	Forwarded to the State Government on 21.11.07.	The State has reported that Jalandhar and Amritsar have been covered during 2007-08. The work in phase-II district was started in field during November, 2007 due to preparatory and other critical activities. The progress has since picked up and improved in the last three months. Upto February, 2008 out of total available funds of Rs. 5081.58 lakh, an amount of Rs. 2371.86 lakh (47%) have been utilized and 15.12 lakh Mandays have been generated.
2.	Ferozepur and Taran Taran	Sh. Jai Singh, President Dalit Dasta Virodhi Andolan, Jalandhar	Refusal to accept application registration and to provide job cards to eligible household in Zeera, Ghal Khurd and Patti block in district Ferozepur and Taran Taran.	Forwarded to the State Government on 16.6.08. NLM was deputed who has reported that the allegation are not proved.	As per report received from State Government the complaint is found base-less.
3.	Hoshiarpur	Shri Roshan Lal and others, Village Gambowal, Tehsil	• Fake entry in job cards. • Keeping job cards in the custody by Sarpanch.	Requested State Government for investigation on	ADC (dev.), Hoshiarpur has reported that enquiry was entrusted to SDM, Dasuha. The SDM Dasuha has reported that an

1	2	3	4	5	6
		Dasuha, District Hoshiarpur	• People not getting work.	05.05.2009.	amount of Rs. 4.90 lakh was given to Gram Panchayat under NREGS. All the 53 job cards holders were given employment. No labour from outside was engaged by the Gram Panchayat. All the 14 complainants were provided employment on their demand. The ADC (dev.) has also reported that the complaint was made due to internal dispute among both the parties. ADC (Dev.) has also recommended that complaint may be filed.
4.	Jalandhar	Shri Ranjit Singh S/o Kawal Singh, Kot Khurd, Gram Panchayat, tehsil, District Jalandhar (East), Punjab	Misappropriation of fund of Rs. 2 lakh by Sarpanch, Praveen Kumar	Forwarded to State Government for investigation on 23.06.2009.	The enquiry was entrusted to ADC (Dev.) Jalandhar who has reported *vide* his letter dated 25.11.09 that the work executed by Gram Panchayat, Kot Khurd under NREGS were got checked by Executive Engineer, Panchayati Raj, Jalandhar and was found proper, Even the social audit of the work has been done. Hence the complaint is without merit and deserves to be filed.
5.	Jalandhar	Shri Ranjit Singh, Gram Panchayat Kot Khurd, Block East, District Jalandhar	Misuse of funds by sarpanch Shri Praveen Kumar, GP Kot Khurd by allowing construction of road in other village Kukar Pind and not in Kot Khurd village	Forwarded to State Government for investigation on 06.07.2009	
6.	Sangrur	Shri Vijay Inder Singla, Member of Parliament	Improper distribution of funds, no work has been provided and	Forwarded to State Government for	ADC (Dev.) Sangrur has reported that the District prepares Panchayat-wise Labour

1	2	3	4	5	6
		(Lok Sabha)	no record of data entry under NREGA Scheme in district Sangrur, Punjab	investigation on 7.11.2009	Budget and work Projection annually and when the funds are received from GOI, these are disbursed to Gram Panchayats Officers (NREGA) In Sangrur District, 549 households have been provided employment and 71893 persondays have been generated. Record of data of Sangrur has been entered on the MIS which may be seen on the NREGA *i.e.* www.nrega.nic.in
7.	Jalandhar	Shri Jai Singh, President, NREGA workers Union, B-1/665, Ranjitgarh Gurudwara Road, Phillaur, District Jalandhar has forward complaints of Mrs. Charanjith Kaur and NREGA Workers Union	Delay in payment of wages in village Sarawan Bodla, Block Mlout, District Mukatsar, Punjab Violation of NREGA, 2005 and non-issuance of job cards in Village, Subhra in Patti Block of District Taran Taran.	Forwarded to State Government for investigation on 22.10.2009	This complaint was sent to ADC (Dev.) Jallandhar who has reported that this matter pertain to District Mukatsar. Now this matter is being forwarded to ADC (Dev.), Mukatsar for making enquiry in this regard.
8.	Ferozepur	Shri Sahib Ram Kadasara, former Sarpanch Gram Panchayat—Ramsra, Tehsil- Abohar, Firozpur District	Issue of bogus job cards	Forwarded to State Government for investigation on 20.08.2009	Reply is awaited

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : सर, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया है, उसकी स्टेटमेंट में लिखा है कि 2006-07 में 3839.21 लाख funds की availability थी, 2500 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ और 1339 लाख unused रहा। इसी तरह 2007-08 में और 2008-09 में भी जो availability of funds है, उसमें इसका एक्सपेंडिचर भी 2000 लाख के करीब हुआ। महोदय, पंजाब में बेरोज़गारों की संख्या में कोई कमी नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका एक्सपेंडिचर क्यों नहीं हो रहा है और प्लान properly execute क्यों नहीं हो रहा है?

श्री सी.पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, NREGA demand-driven scheme है। लोग काम मांगते हैं, तब उनको काम देते हैं। As per the Act, दिसंबर महीने में लेबर बजट बनाकर भारत सरकार को भेजना पड़ता है। वहां से भारत सरकार द्वारा लेबर बजट पाने के बाद जितनी डिमांड होती है, उतना पैसा वहां पर खर्च होता है। इसी आधार पर वहां की सरकार ने उस डिस्ट्रिक्ट में जितने proposal भेजे, उस हिसाब से पैसा रिलीज़ किया। वहां पर काम नहीं हो पाया, इसलिए इसका पैसा बचा हुआ है। इसमें बजट एलोकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है।

SHRI AVTAR SINGH KARIMPURI: Sir, the reply is not satisfactory. As per facts available, हमारे पंजाब में टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में 35,512 households को employment दिया गया है। Hoshiarpur is one leading district, लेकिन पंजाब में ही लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है, जिसने केवल 996 households को employment दिया है। तो जो गैप है, वह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की lacking की वजह से है। वह स्कीम को sincerity से लागू न करने के कारण है। अभी भी इस साल की जो स्कीम है, उसमें भी जो मोगा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भी सिर्फ 932 परिवारों को employment दिया है, जबकि मोगा गरीबी के लिहाज़ से शायद पंजाब में सबसे आगे होगा। क्या वहां के लोग रोज़गार नहीं चाहते हैं? लोग रोज़गार चाहते हैं, लेकिन सरकार की मशीनरी में कुछ कमियां हैं। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से आश्वासन चाहूंगा कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट economically forward डिस्ट्रिक्ट है और वहां 35,512 households को employment मिला है....

श्री सभापति : सवाल पूछिए।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : मेरा सवाल यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट इस स्कीम को लागू नहीं कर रहे हैं, क्या आदरणीय मंत्री जी यह एश्योरेंस देंगे कि उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट की तरह आगे बक़्कर वे इस स्कीम को लागू कराएंगे?

श्री सी.पी. जोशी : महोदय, यदि वहां काम करने वाले व्यक्ति available हैं और सरकार उनको काम नहीं दे रही है, तब तो हम इसमें intervene कर सकते हैं, लेकिन लगता है कि वहां काम मांगने वालों की संख्या कम है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके पास यदि कोई स्पेसिफिक जानकारी हो कि जो कार्ड बने हुए हैं, उनको सरकार काम नहीं दे रही है, तो वह आप मुझे दें। तभी भारत सरकार राज्य सरकार से उस संबंध में कुछ बात करेगी।

श्री अवतार सिंह करीमपुरी : Information provide करवा देंगे।

श्री ईश्वर सिंह : चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वैसे तो यह पंजाब का सवाल है, लेकिन ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना में अनियमितताएं बहुत आ रही हैं। हमारा वास्ता देहात से बहुत ज्यादा है और मंत्री जी ने अभी बताया कि देहात के अंदर काम ज्यादा है और काम करने वाले कम हैं।

श्री ईश्वर सिंह (क्रमागत) : मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सरकार के विचाराधीन है कि जिस गांव में रॉ मैटीरियल मिलता है, वहां पर ट्रेनिंग देकर रोजगार गारंटी योजना उन्हीं को दी जाए, विशेषकर उसी इलाके के लोगों को रोज़गार दिया जाए।

श्री सी.पी. जोशी : महोदय, मैं समझता हूं कि हम सबको मिलकर लोगों को जानकारी देने की आवश्यकता है कि यह वह स्कीम है, जिसमें पैसे की कमी नहीं है। जितने लोग काम करना चाहते हैं, उनको काम मिलेगा। यदि जागरुकता नहीं है तो हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स की ड्यूटी बनती है कि उनमें जागरुकता लाएं और जिन लोगों को जॉब की आवश्यकता है, उनको जॉब मिले। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मेरी इस भावना से सहमत होंगे और मेरी जानकारी में अगर वे कुछ और बात लाएंगे तो हम निश्चित तौर पर उस पर और कार्यवाही करेंगे।

श्री ईश्वर सिंह : मैंने पूछा कि क्या आप वहां ट्रेनिंग देने जा रहे हैं?

श्री बलबीर पुंज : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि पंजाब में जो वेज़िज़ हैं, जो दिहाड़ी है, वह डेढ़ सौ, पौने दो सौ रुपए तक की है और जो आपकी योजना है, उसमें जो दिहाड़ी दी जाती है, प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है, वह सौ रुपए है? इस कारण से - क्योंकि आपकी मजदूरी का रेट कम है और बाजयर में मजदूरी ज्यादा मिलती है - इस योजना में बहुत सारे लोगों को रोज़गार उपलब्ध नहीं हो रहा है। क्या यह भी सत्य नहीं है कि पंजाब सरकार ने आपसे निवेदन किया है कि इस योजना का जो प्रारूप है, वह प्रदेशानुसार बदला जाए और पंजाब की जो परिस्थिति है, उसके हिसाब से वहां पर यह योजना लागू की जाए जिससे ये जो आंकड़े, आपको अलग-अलग जिलों में नज़र आ रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर अभी तक मुश्किल से 61 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च हुए हैं, वहां पर भी लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, इस योजना को बनाने के पीछे मंशा यह थी कि गांव में रहने वाले गरीब आदमी को हम सौ दिन रोज़गार की गारंटी का assurance दें। अब wages से इसका संबंध नहीं है। जो prosperous states हैं, उनके minimum wages ज्यादा हैं। Minimum wages का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। जहां-जहां पर भी इन दोनों के बीच में अंतर है, वहां पर लोग प्राइवेट में काम करने जा रहे हैं और इस योजना के अंतर्गत काम करने नहीं आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि दोनों चीजयें के बीच अंतर समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार उन गरीब आदमियों को, जिनको lean period के अंदर काम नहीं मिलता है, उनको काम देने के लिए यह कानून बनाया गया है।

श्री बलबीर पुंज : क्या पंजाब सरकार ने इस बारे में उनको आवेदन किया है? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग था कि...**(व्यवधान)** ...

श्री सभापति : एक समय में एक ही सवाल कीजिए।

श्री बलबीर पुंज : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग था कि क्या पंजाब सरकार ने आपसे निवेदन किया है कि इस योजना पर पुनः विचार करें?

श्री सी.पी. जोशी : यह पंजाब सरकार का सवाल नहीं है। पूरे भारत के अंदर यह योजना लागू है। जिस स्टेट में यह अंतर है, वहां पर इस योजना के अंतर्गत काम कम हो रहा है। जहां पर जॉब की आवश्यकता है, वहां पर हमने ensure किया है कि हम 100 रुपए तक देंगे। जो भी आदमी काम करने आएगा, उसको 100 रुपए का assurance है, बाकी को जहां ज्यादा मिल रहा है, वहां काम करें।

श्रीमती वृंदा कारत : क्या आपने 100 रुपए minimum wage कर दिया है? ..**(व्यवधान)**..

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: You ensure hundred rupees. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please don't intervene. ...*(Interruptions)*... Please don't intervene. ...*(Interruptions)*... Don't intervene in the... ...*(Interruptions)*... Please listen.

SHRI MOINUL HASSAN: Sir, hundred rupees is not... ...*(Interruptions)*...

श्री सी.पी. जोशी : आप लोग सुनिए तो सही। ...**(व्यवधान)**... महोदय, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले यह आश्वासन दिया था।...**(व्यवधान)**... आप सुन तो लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती वृंदा कारत : यह कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please. *(Interruptions)* It is a national scheme. *(Interruptions)*

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Mr. Chairman, Sir, this is not something... ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति : आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... It is a national scheme. *(Interruptions)* Please. *(Interruptions)* Please.

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। यह सारे भारतवर्ष का सवाल है।..(व्यवधान)..

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Sir, the Minister is... ...*(Interruptions)*...

श्री रुद्रनारायण पाणि : सभापति महोदय...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please. *(Interruptions)* One minute. *(Interruptions)* आप ज़रा एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**... One minute. *(Interruptions)* The question relates to a national scheme of the Government. *(Interruptions)*

श्री रवि शंकर प्रसाद : कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है। ...**(व्यवधान)**... आप थोड़ा संतोष रखिए। ..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: I think, no further discussion on this. *(Interruptions)* Please. *(Interruptions)*

श्री रवि शंकर प्रसाद : आप भारत सरकार के मंत्री हैं। ...**(व्यवधान)**... The Minister must know it. *(Interruptions)*

SHRI C.P. JOSHI: I am a Minister of the Government of India. I am aware about it. *(Interruptions)*

श्री सभापति : आप प्लीज़ बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि : सरकारी पैसे से सबसे ज्यादा पार्टी का काम करते हैं।...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: I am sorry to say ..*(Interruptions)*..

श्री सी.पी. जोशी : सर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में यह कहा कि हम सौ रुपए देंगे। आज सरकार में आने के बाद मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)**... हम सौ रुपए देंगे। जो भी सरकार की घोषणा थी, उसको लागू किया।...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद : ये कांग्रेस के मंत्री नहीं हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप जरा बैठ जाइए। देखिए, ...**(व्यवधान)**... Please बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... Please ..*(Interruptions)*.. Please ..*(Interruptions)*..

SHRI C.P. JOSHI: I am aware of this. ..*(Interruptions)*.. I am aware of this. ..*(Interruptions)*.. Don't worry about this. ..*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: I am sorry to say ..*(Interruptions)*.. I am sorry ..*(Interruptions)*..

SHRI C.P. JOSHI: I am a Minister of Government of India. ..*(Interruptions)*.. I am a responsible man. ..*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: One minute, please. ..*(Interruptions)*.. Leader of the Opposition is saying something. ..*(Interruptions)*.. Please ..*(Interruptions)*..

SHRI ARUN JAITLEY: I have a point of order, Sir. ..*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: Please ..*(Interruptions)*..

SHRI C.P. JOSHI: I am a responsible man. ..*(Interruptions)*.. It is my party's commitment, not your party's commitment. ..*(Interruptions)*.. It is my party's commitment to the people of the country. ..*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: Please ..*(Interruptions)*.. The Leader of Opposition. ..*(Interruptions)*..

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I have a point of order. Sir, each one of us is expected to maintain a certain quorum or dignity. But we expect certain exemplary conduct from Ministers. After you have almost directly indicated that the Minister must answer on behalf of the Government, he is not standing here as a spokesman of a party; he is standing here as a Minister of the Government, this is still not a sufficient clue to the Minister to discipline himself and he now starts answering as though this is a street meeting that he is addressing on behalf of his party. ..*(Interruptions)*..

SHRI C.P. JOSHI: Sir, I am very sorry. ..*(Interruptions)*.. He is a senior leader. ..*(Interruptions)*.. We have gone to the people of this nation ..*(Interruptions)*.. What is wrong in it? ..*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: Please ..*(Interruptions)*.. Let us get on with the Question Hour. ..*(Interruptions)*.. Please ..*(Interruptions)*.. All right ..*(Interruptions)*.. Okay ..*(Interruptions)*..

श्री रुद्रनारायण पाणि : लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। .. **(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please resume your places. ..*(Interruptions)*.. Let's get on with the Question Hour. ..*(Interruptions)*.. Please ..*(Interruptions)*.. Please ..*(Interruptions)*.. Just one minute. ..*(Interruptions)*..

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: Sir, he should apologise. ..*(Interruptions)*..

SHRIMATI BRINDA KARAT: *

MR. CHAIRMAN: Please ..*(Interruptions)*.. This is not on record. ..*(Interruptions)*..

SHRI C.P. JOSHI: Madam, I have said in the House that from first April 2008, we are committed to give one hundred rupees ..*(Interruptions)*.. We will give it. ..*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Please resume your places. ..*(Interruptions)*..

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, my request is, after the hon. Chair has said something, the Minister should not provoke others. ..*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: Let us get on with the Question Hour. ..*(Interruptions)*..

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I only request the Chair to direct the Minister to withdraw the statement. ..*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: Please ..*(Interruptions)*.. Let's get on with the Question Hour. ..*(Interruptions)*..

---

*Not recorded.

श्री एम0 वेंकैया नायडु : कांग्रेस कहां से आ गई ? ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please ..*(Interruptions)*.. Mrs. Karat, please ..*(Interruptions)*.. I request you to resume your places. ..*(Interruptions)*.. Dr. Malaisamy, does your supplementary relate to this question? ..*(Interruptions)*.. It relates to Punjab? ..*(Interruptions)*..

DR. K. MALAISAMY: Sir, it directly relates to this question. ..*(Interruptions)*.. I will come to this. ..*(Interruptions)*.. Sir, as far as the scheme is concerned, the CAG has conducted a performance audit some time back. During the audit, the auditor has made an observation that though the scheme is laudable in letter and spirit, it has been badly implemented. I mean, he has illustrated it in several ways. On of the ways that, I am coming to the question, the person who is seeking employment after he is registered. But he has not been given the employment. With the result he has to wait. The law says, the Act says that during the time of non employment after registration, he has to be paid. But he has not been paid.

MR. CHAIRMAN: What's the question?

DR. K. MALAISAMY: There are several illustrations like this. May I know from the Minister whether these kinds of lapses have been corrected or not?

SHRI C.P. JOSHI: Sir, such lapses have been corrected and the few States have paid the dues as per the provisions of the Act. There are examples of few States which have paid it.

We are adhering to the provision given in the Act. If they are not giving jobs, after 15 days, the State Government is paying unemployment allowance. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: All right. *(Interruptions)* No argumentation, please. *(Interruptions)* No arguments. Question No.164.

Rise in prices

*164. SHRI RAJEEV SHUKLA:††
DR. T. SUBBARAMI REDDY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether rising prices of food articles and certain manufactured items have pushed up inflation past the one per cent mark to 1.21 per cent in October, 2009;

(b) whether having remained in negative territory for 13 straight weeks during 2009, mainly owing to high base effect, the whole-sale price index based inflation changed its course to move into the positive zone in the month of September;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) what are the steps taken by Government to control rise of prices to check inflation?

---

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rajeev Shukla.